रामजल सेतु परियोजना के लिये बारां में भूमि आवंटन को मंजूरी

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने बारां के साथ रीको को पेट्रोज़ोन के लिये बोरावास में भूमि आवंटन का निर्णय लिया।

जयपुर, 24 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में ईआरसीपी परियोजना, जिसका नया नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना है, के कार्यों को गति प्रदान करने और बारां जिले में जनजाति बहुल क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भूमि आवंटन के महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। शर्मा ने रीको को राजस्थान पेट्रोज़ोन की स्थापना के लिए भूमि आंवटन की स्वीकृति भी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2024-25 के क्रम में, कोटा संभाग में बालिका सैनिक विद्यालय की स्थापना के लिए कोटा जिले की रामगंजमण्डी तहसील में 22 हैक्टेयर भूमि का आंवटन स्कूल शिक्षा विभाग को करने की स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी परियोजना के अन्तर्गत, बांरा जिले में रामगढ एवं महलपुर बैराज के निर्माण से डूब क्षेत्र में होने वाले विस्थापितों एवं प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने हेतु आबादी के लिए ग्राम कोयला में 35 हैक्टेयर भूमि आंवटन की स्वीकृति प्रदान की। इसी प्रकार, वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत तहसील शाहाबाद की 381 हैक्टेयर भूमि एवं तहसील किशनगंज की 551 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को आंवटित करने की मंजूरी दी गई है, इससे ईआरसीपी परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध हो सकेगी।

एक अन्य निर्णय के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों की महत्वाकांक्षी पीएम जनमन योजना के तहत बारां जिले की स्वीकृत 14 सड़कों के निर्माण के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन के अंतर्गत 21 हैक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोज़ोन की स्थापना के लिए रीको को पचपदरा तहसील (बालोतरा) के ग्राम बोरावास में 97 हैक्टेयर भूमि और ग्राम बागुण्डी में 26 हैक्टेयर भूमि के आंवटन की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

स्वास्थ्य ठीक होते ही राहुल दिल्ली में प्रचार करेंगे

नयी दिल्ली, 24 जनवरी। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तबीयत नासाज है, जिसके कारण वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जैसे ही स्वस्थ होंगे, वे तेजी से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों के सवाल पर कहा कि गांधी की तबीयत नासाज है और वह जैसे ही स्वस्थ होंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार आरंभ कर देंगे।

पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव प्रचार में नहीं उतरने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार हैं और जब प्रचार तेज होगा तो वे भी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार शुरू कर देंगी।

मुख्यमंत्री ने लाइम स्टोन व लैड-ज़िंक ब्लॉक की ई-नीलामी को अनुमति दी

■ इस अनुमति के बाद जैसलमेर, कोटा तथा सवाई माधोपुर जिले के ब्लॉक की अधिसूचना जारी होगी।

■ हाल ही कोणार्क में आयोजित नैशनल माइन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रैंस में वर्ष 2023-24 में देश में सर्वाधिक मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन करने पर राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

जयपुर, 24 जनवरी। जैसलमेर, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में विभिन्न खनिज ब्लॉक्स की ई-नीलामी हेतु अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन लाईमस्टोन खनिज ब्लॉक्स एवं लैड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की अनुमति का अनुमोदन किया है।

मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त अब जैसलमेर जिले में खनिज लाईमस्टोन के ब्लॉक पारेवार (-) 960 हैक्टेयर क्षेत्र, पारेवार (-) 928 हैक्टेयर क्षेत्र, पारेवार (-) 960 हैक्टेयर क्षेत्र एवं पारेवार-ए (400 हैक्टेयर क्षेत्र), कोटा जिले में लाईमस्टोन के पूर्वेक्षित ब्लॉक निनामा-दुनिया एक्सटेंशन (408.2974 हैक्टेयर क्षेत्र), जैसलमेर जिले में लाईमस्टोन के खाबिया (200.4766 हैक्टेयर क्षेत्र) एवं खाबिया ईस्ट ब्लॉक (205.9798 हैक्टेयर क्षेत्र) और सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में लेड-जिंक ब्लॉक (984.5951 हैक्टेयर क्षेत्र) के कम्पोजिट लाइसेंस में ई-नीलामी की अधिसूचना जारी की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में मिनरल ब्लॉक्स के ऑक्शन में पूरे देश में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। ओडिशा के कोणार्क में हाल ही आयोजित नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2023-24 में देश में सर्वाधिक मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन पर राजस्थान को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। पिछले एक साल में खनन क्षेत्र में खनिज खोज से लेकर माइनर एवं मेजर मिनरल ब्लॉक्स के ऑक्शन, एमनेस्टी योजना, ड्रोन सर्वे और एकबारीय समाधान योजना, नई और प्रगतिशील खनिज नीति, एम-सैण्ड नीति से प्रदेश में खनन उद्यमियों एवं खननकर्ताओं में निवेश का सकारात्मक माहौल बना है।

राज्य सरकार के प्रयासों से गत वित्त वर्ष में खनन क्षेत्र में 7 हजार 460 करोड़ 48 लाख रूपये का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 31 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की गई, जिनमें से वर्तमान राज्य सरकार के पहले तीन माह में ही 15 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी केन्द्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से की गई। वर्तमान में प्रदेश में खनन क्षेत्र में लगभग 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान खनिज नीति-2024 एवं एम-सेण्ड नीति-2024 लाकर महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए गए हैं। इसके माध्यम से राज्य जीडीपी में खनन क्षेत्र की हिस्सेदारी को 3.4 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2029-30 तक 5 प्रतिशत और 2046-47 तक 8 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। साथ ही, इन नवाचारों से खनन क्षेत्र में रोजगार सृजन को भी गति मिलेगी।

कोलकाता रेप मर्डर केस, हाईकोर्ट में अपील की सीबीआई ने

सीबीआई ने अपील के आरोपी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग की है

■ आरोपी संजय रॉय को सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

कोलकाता, 24 जनवरी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर आरजी कर अस्पताल के प्रशिक्षु डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले दोषी करार दिये गये सिविक वालंटियर संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की। संजय रॉय को एक सत्र अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सीबीआई का नवीनतम कदम पश्चिम बंगाल सरकार की मंगलवार की याचिका पर आपत्ति जताने के बाद हुआ, जिसमें सियालदह की सत्र अदालत द्वारा सिविक वालंटियर को हत्या का दोषी पाए जाने और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद रॉय के लिए मौत की सजा की भी मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली युगल पीठ के समक्ष यह मामला सीबीआई के अधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने पेश किया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कहा कि एजेंसी ने शुक्रवार को मामले की ई-फाइलिंग पूरी कर ली है और उम्मीद है कि सोमवार को मामला सामने आएगा। इससे पहले, सत्र न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिर्बान दास ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

गौरतलब है कि एक 31 वर्षीय महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ नौ अगस्त की सुबह उसके कार्यस्थल आरजी कर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर व्यापक धारणा थी कि एक से अधिक लोगों ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, लेकिन उपलब्ध सबूत मिलने के बाद, संजय रॉय एकमात्र अपराधी के रूप में उभरा और मामले में 50 गवाह पेश हुए।

'दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल वासियों के लिये अलग मंत्रालय बनायेंगे'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की

■ कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के लोगों का इस्तेमाल वोट बैंक की तरह करते हैं। उनके उत्थान के लिये कुछ नहीं करते।

नयी दिल्ली, 24 जनवरी। कांग्रेस ने दिल्ली की सत्ता में आने पर पूर्वांचल के लोगों के उत्थान के लिए अलग मंत्रालय बनाने और बजट का प्रावधान करने का वादा किया है!

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्वांचल का सूर्योदय नाम से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने की। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सोशल मीडिया की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत, कन्हैया कुमार, प्रणव झा और अभय दुबे उपस्थित थे।

सिंह ने कहा दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। मैं चुनाव प्रचार के लिए कल संगम विहार गया था, जहां पाया कि पूर्वांचल के लोग बदहाल स्थिति में रह रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के लोगों का इस्तेमाल वोट बैंक की खातिर करती है, लेकिन पूर्वांचल के लोगों के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं करती है।

उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आती है तो पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। इसके लिए बजट का भी निर्धारण किया जाएगा।

श्रीनेत ने कहा कि पूर्वांचलियों ने देश के कोने-कोने में जाकर देश में सृजन करने का काम किया है, लेकिन जब पूर्वांचलियों के हक की बात आती है तो उनके साथ बेईमानी की जाती है।

उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, हम भूले नहीं हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यूपी-बिहार के लोग 500 रुपये का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख का इलाज करवाते हैं।

उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहने का पाप बीजेपी करती है।

उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोग न सिर्फ पूर्वांचल का गौरव बढ़ाते हैं, बल्कि वे इस देश के नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं उन्होंने कहा कि 30-35 लाख लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

ऐसे में उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सहित, तमाम मुद्दों के लिए अलग से विभाग होना चाहिए, इसलिए अगर हम दिल्ली की सत्ता में आए तो पूर्वांचल के लोगों के अलग मंत्रालय बनायेंगे और बजट का प्रावधान होगा।

जन्मजात ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था, क्योंकि चाइनीज़ एक्सक्लूज़न एक्ट के तहत, वे अमेरिकी नागरिक नहीं थे। फिर यह मामला कोर्ट में गया था। इमिग्रेशन पर प्रतिबंधों के समर्थकों का कहना है कि यह मामला उन बच्चों पर लागू होता है जो कानूनन अप्रवासी माता-पिता की संतान थे। पर यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह उन बच्चों पर भी लागू होता है, जिनके माता-पिता अवैध रुप से अमेरिका में रह रहे हैं।

ब्यावर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, खसरा संख्या 16 के खातेदार रेवतराम पुत्र मालाराम मेघवाल निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर एवं पलपाराम पुत्र रामेश्वरलाल बलाई निवासी लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर रकबा 2.1288 हैक्टर होना पाये गये।

'नरेश मीणा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाकर्ता ही मामले का मुख्य आरोपी है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वीडियो से अदालत को पूर्वाग्रह से ग्रसित किया जा रहा है। मामले में चार एफआईआर दर्ज हुई हैं और दो मामलों में पुलिस ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया है। ऐसा लगता है कि सरकार उसे किसी भी तरह जेल में रखना चाहती है। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी।

याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा और अधिवक्ता फतेह राम मीणा ने बताया कि उप चुनाव के दौरान एसडीएम से मारपीट के आरोप में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच गतिरोध बना था। इस पर टोंक की नगरफोर्ट थाना पुलिस ने याचिकाकर्ता सहित, दर्जनों अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। याचिका में कहा गया कि घटना के समय याचिकाकर्ता पुलिस अभिरक्षा में था। ऐसे में वह लोगों को कैसे उकसा सकता है। इसके अलावा प्रकरण में 18 आरोपियों की टोंक के सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है, जबकि हाईकोर्ट ने भी करीब 40 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

"इन्डैम्निटी अंडरटेकिंग"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बीमा, राजस्थान भंडारण निगम अपने खर्च पर करवा ले और बाद में ऑरिगो कंपनी को जो राशि भुगतान की जानी है, उसमें से इसकी कटौती कर ली जाये।

मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने माना कि, इन दोनों कंपनियों ने शर्तों का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार की अरबों रु. की कृषि उपज और आमजन में वितरित की जाने वाली खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाला है। दोनों कंपनियों के इस कारनामे से राजस्थान में महंगाई वृद्धि का खतरा भी बढ़ गया है।

गौरतलब है कि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने गत 16 मई 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शिकायती पत्र लिखकर इन दोनों कंपनियों को भंडारण निगम में ठेका देने की आड़ में करीब 150 करोड़ रु. का घोटाला बताया था। किरोड़ीलाल मीणा के आरोप थे कि, कल्पतरू समूह से जुड़ी यह दोनों कंपनियां श्री शुभम लॉजिस्टिक व ऑरिगो कोमोडिटीज़ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करीबी हैं। इन कंपनियों को ठेका देने के लिए राज्य भंडारण निगम के तत्कालीन अफसरों ने कई तरह के नियम-कायदों का उल्लंघन किया और इन कंपनियों को अवांछित फायदा पहुंचाया। ठेका लेने के बाद इन कंपनियों ने भी करीब 150 करोड़ रु. का घोटाला किया। साथ ही आमजन को वितरित किए जाने वाली खाद्य सामग्री जिसकी कीमत करीब 3000 करोड़ रु. थी, को गोदामों में बिना किसी बीमा के ही पटककर रखा। आज भी यही स्थिति है।

उल्लेखनीय है कि, श्री शुभम लॉजिस्टिक व ऑरिगो कॉमोडीटिज़ तथा राज्य भंडारण निगम के बीच का विवाद "आर्बिट्रेशन" में लंबित है, जहां एक तरफ शुभम लॉजिस्टिक करीब 70 करोड़ रु. का भुगतान मांग रही है, वहीं दूसरी ओर अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की एवज में भंडारण निगम ने इस कंपनी पर 202 करोड़ रु. का दावा ठोक रखा है।

ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2024 को श्री शुभम लॉजिस्टिक को चेताया था कि वह 48 गोदामों का सही श्रेणी में बीमा करवाये, इसके बावजूद भी इस कंपनी ने जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना की। इसके अलावा 25 अप्रैल से 12 जून 2024 तक की अवधि में भी श्री शुभम लॉजिस्टिक के 48 गोदामों का कोई बीमा नहीं था।

उत्तराखंड में भूकंप के झटके

■ उत्तरकाशी में शुक्रवार सुबह 3.5 तीव्रता के भूकम्प के दो झटके आए।

उत्तरकाशी, 24 जनवरी। शुक्रवार को पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में सुबह-सुबह भूकंप के झटकों ने लोगों को दहला दिया है। ये भूकंप उत्तरकाशी में आया है। भूकंप के झटके लगने के बाद लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उत्तरकाशी में गुरुवार को सुबह 8 बजकर 19 मिनट पर भूकंप के झटके लगे हैं। इस भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई है। इससे पहले सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर कम तीव्रता का भूकंप आया था। इसकी तीव्रता 2.7 दर्ज की गई थी।

उत्तरकाशी में दूसरे भूकंप का झटका बेहद तेज था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वरूणावत पर्वत के भूस्खलन संभावित क्षेत्र से पत्थर भी गिरने लगे। डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। हालांकि, गुरुवार को आए इस भूकंप के कारण अब तक किसी भी जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों के बाद, जिले के डीएम डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट ने अधिकारियों को सभी क्षेत्रों से इसके संबंध में जानकारी लेने का निर्देश जारी किया है। इस भूकंप ने लोगों को 1991 के विनाश की याद दिला दी है। आपको बता दें कि, उत्तरकाशी में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप ने क्षेत्र में बड़ा विनाश मचाया था।

ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनीं

■ बॉलीवुड की प्रसिद्ध हीरोइन रह चुकी ममता कुलकर्णी ने काफी समय पहले संयास ले लिया था।

प्रयागराज, 24 जनवरी। कभी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रह चुकीं ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शुक्रवार को ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनीं। पहले उन्होंने संगम में अपना पिंडदान किया। फिर अखाड़े में ही उनका पट्टाभिषेक हुआ। ममता ने काफी पहले संन्यास ले लिया था। वो साध्वी की जिंदगी जी रही थीं। हाल ही में वो 24 साल बाद भारत लौटी हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्हें नया नाम भी मिला है। अब वह ममता नंद गिरि के नाम से पहचानी जाएंगी।

ममता कुलकर्णी

2015 में स्थापित किन्नर अखाड़ा एक हिंदू धार्मिक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता और मान्यता देना है। अब, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के रूप में नियुक्त करके अखाड़ा अपने संदेश और प्रभाव को और अधिक फैलाने कोशिश कर रहा है।

किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, "ये महादेव का आदेश था। महाकाली की इच्छा थी। ये मेरे गुरु का आदेश था। उन्होंने ही आज का दिन चुना। मैंने कुछ नहीं किया है... सब ईश्वर की मर्जी है।"

किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने ममता नंद गिरी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़े ने बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया है। उनका नाम श्री माई ममता नंद गिरि रखा गया है। वह पिछले डेढ़ साल से किन्नर अखाड़े और मेरे संपर्क में हैं। अगर वे चाहें तो किसी भी धार्मिक पात्र का किरदार निभा सकती हैं, क्योंकि हम किसी को भी अपनी कला दिखाने से नहीं रोकते।"

रक्षा मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली "संजय" को हरी झंडी दिखाई

नयी दिल्ली, 24 जनवरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को 'युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली - संजय' (बीएसएस) को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 'संजय' एक स्वचालित प्रणाली है, जो सभी जमीनी और हवाई युद्धक्षेत्र में लगे सेंसरों से जानकारी को एकीकृत करती है।

यह प्रणाली जानकारियों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए उन्हें संधारित करती है, दोहराव को रोकती है और उन्हें सुरक्षित सेना डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट संचार नेटवर्क पर युद्धक्षेत्र की निगरानी परिदृश्य बनाने के लिए संबद्ध करती है। इस प्रणाली से युद्धक्षेत्र के बारे में जानकारी बढ़ेगी और एक केंद्रीकृत वेब एप्लिकेशन के माध्यम से भविष्य के युद्धक्षेत्र के बारे में कमान और सेना मुख्यालय को जानकारी भेजी जायेगी।यह प्रणाली अत्याधुनिक सेंसर और अत्याधुनिक एनालिटिक्स से लैस है।

महाराष्ट्र की ऑर्डिनैंस फैक्टरी में विस्फोट में 8 मरे

■ भंडारा जिले में विस्फोट से फैक्टरी की एक इकाई की छत गिर गई जिसमें कई श्रमिक फंस गये।

मुंबई, 24 जनवरी। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शुक्रवार को सुबह एक आयुध फैक्टरी में विस्फोट हो गया। हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि सात को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आयुध फैक्टरी में विस्फोट के कारण एक इकाई की छत गिरने से कई श्रमिक फंस गए। उन्होंने विस्फोट में जान गंवाने वालों के लिए शोक भी व्यक्त किया।

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भंडारा में आयुध फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ है।

इससे पहले, जिलाधिकारी संजय कोल्टे ने बताया कि विस्फोट सुबह करीब साढ़े 10 बजे आयुध के परिसर में हुआ। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट जवाहर नगर इलाके में स्थित फैक्टरी के 'एलटीपी सेक्शन' में हुआ। विस्फोट के समय 'एलटीपी सेक्शन' में 14-15 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें से तीन को बचा लिया गया और एक की मौत हो गई। अग्निशमन दल और एंबुलेंस को मौके पर भेज दिया गया है। छत ढ ह गई है, जिसे जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। हादसे की खबर आते ही फड़णवीस ने दुख जताया। उन्होंने कहा, भंडरा जिले में आयुध फैक्टरी में हुए विस्फोट में छत गिरने से 13 से 14 श्रमिकों के फंसने की खबर है।

'ईडी व एसीबी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस मामले में गणपति ट्ययूबवेल व श्री श्याम कृपा कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी कम्पलीशन सर्टिफिकेट के जरिए, इस योजना के करीब 900 करोड रुपए के टेंडर लिए थे।

इस संबंध में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने जल जीवन मिशन के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को दो बार पत्र लिखे कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर लिए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने मामले में तब कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद, याचिकाकर्ता संस्था ने पुलिस कमिश्नर व एसीबी को कई बार पत्र लिखे, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि इस मिशन में घोटाला उजागर होने के बाद टीएन शर्मा के परिवाद पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस पर अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि केवल दो फर्मों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि इस प्रकार के फर्जीवाड़े को लेकर शिकायतकर्ता ने अन्य के खिलाफ भी शिकायत की है, लेकिन उन अफसरों व अन्य लोगों को बचाया जा रहा है और उनका नाम एफआईआर में नहीं है।

दूसरी ओर, ईडी की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी ने कहा कि मामले में बड़ा घोटाला हुआ है। इस पर अदालत ने ईडी और एसीबी से मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है।

वक्फ बिल जेपीसी से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विधेयक का उद्देश्य "वक्फ सम्पत्तियों को नष्ट करना" है।

मसूद ने कहा, "वे पहले ही दिन से, हर काम में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे वक्फ सम्पत्तियों को छीनना चाहते हैं। हम 25 तथा 26 जनवरी को मीटिंग करने के लिये सहमत थे, अब उन्होंने इसे 27 जनवरी के लिये खिसका दिया है। वे मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। वे कतई गंभीर नहीं हैं, वे तो वक्फ सम्पत्तियों को बस तबाह कर देना चाहते हैं। हम सब चाहते थे कि 27 जनवरी को होने वाली मीटिंग को आगे खिसका कर, 31 जनवरी को कर लिया जाये। जेपीसी के अन्दर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।"

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, जो निलम्बित किये गये हैं, ने भी यही चिन्ताएं दोहराईं। उन्होंने विधेयक के पीछे छिपे इरादों पर सवाल खड़े किये तथा आरोप लगाया कि यह विधेयक आरएसएस के एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने कहा, "हमें रात के 11:30 बजे मैसेज मिला कि 25 जनवरी को होने वाली मीटिंग खिसका कर 27 जनवरी को कर दी गई हैं। क्या इस तरह से सांसदों का समय बरबाद करना सही है? सदस्य विभिन्न राज्यों से यहाँ आये हैं। क्या हम अपने चुनाव क्षेत्र की जनता के साथ गणतंत्र दिवस नहीं मनाएं? यह वक्फ विधेयक मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों की जमीन को छीनने के लिये लाया गया है। आरएसएस एक एजेंडा चला रही है कि जिस स्थान पर नमाज पढ़ी जाती है, वह वक्फ की जमीन हो जाती है। हमने संसद में "बिस्मिल्लाह" के साथ शपथ ली थी, तो क्या इससे वह वक्फ की जमीन हो गई? क्या हम संसद भवन पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे? लोगों को भ्रमित किया जा रहा है।" इस बीच, पाल ने स्पष्ट किया कि मीरवाइज़ उमर फारूक, जो कश्मीर के मुख्य काज़ी (चीफ क्लेरिक) हैं, के नेतृत्व में आया प्रतिनिधिमंडल मीटिंग में मौजूद था तथा प्रतिनिधिमंडल अपने विचार कमेटी के समक्ष रखना चाहता था। पाल ने कहा कि 27 जनवरी को विधेयक पर धारा-वार चर्चा होनी है तथा कमेटी की अंतिम रिपोर्ट संसद के बजट सत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

ग्रामीणों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बीकानेर में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बैंक किट भी बरामद किए हैं। पुलिस ने समर्थ सोनी (32) निवासी बी-129 वल्लभ गार्डन जेएनवीसी, धर्मनारायण सिंह (24) व शिवनारायण सिंह (29) निवासी एफ-32 वल्लभ गार्डन, रोहित सिंह (25) निवासी वाई 31 सुदर्शना नगर मोना बिल्डिंग, विकास बिश्नोई (29) निवासी फुलासर और गुरुदेव बिश्नोई (25) निवासी मुक्ता प्रसाद नगर को गिरफ्तार किया है।

पेरिस क्लाइमेट डील से ट्रम्प का हटना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में पारंपरिक जीवाश्म ईंधन को प्राथमिकता देते हैं।

सन् 2024 में एक अध्ययन में यह सुझाव दिया गया कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एल.एन.जी.) उत्पादन और निर्यात का विस्तार उपभोक्ता लागतों को बढ़ा सकता है और साथ-साथ पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इस बीच, ट्रंप ने, इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के बाइडन के प्रयास को, उपभोक्ताओं की पसंद का हवाला देते हुए उलट दिया, लेकिन संभावना है कि तेल और गैस के लिए बाज़ार बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। उन्होंने घरेलू उपकरणों के लिए एनर्जी एफिशिएन्सी स्टैण्डर्ड्स को भी समाप्त कर दिया और सभी संघीय नीतियों की समीक्षा का आ ान किया, जो उनके अनुसार, घरेलू ऊर्जा संसाधनों के विकास या उपयोग में रुकावट डालती हैं, तेल, गैस, कोयला, जल विद्युत, बायोफ्यूल, महत्वपूर्ण खनिजों और परमाणु ऊर्जा को प्राथमिकता देते हुए।

तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, जैसे भारत के लिए, पेरिस समझौते से अमेरिका का हटना, आर्थिक वृद्धि पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है।

अमेरिका द्वारा वैश्विक जीवाश्म ईंधन की मांग बढ़ सकती है, जिससे तेल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं या बढ़ सकती हैं। एक बड़ा तेल आयातक होने के कारण भारत को ऊर्जा लागतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है, जिससे औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति प्रभावित हो सकती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम होने से भारत का नवीकरणीय (रिन्युएबल) ऊर्जा में परिवर्तन धीमा हो सकता है, जिससे इसके आर्थिक लाभ, जैसे कि हरित क्षेत्रों में नौकरी सृजन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता में देरी हो सकती है।

अमेरिका के हटने से अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट फायनैंस मैकनिज़्म में उसका योगदान कम हो जाएगा। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ इस वित्तीय सहायता पर निर्भर करती हैं, ताकि स्वच्छ ऊर्जा पहलों, जलवायु अनुकूलन और शमन परियोजनाओं का समर्थन किया जा सके। वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं पर अनिश्चितता से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और सतत बुनियादी ढांचे के लिए निजी निवेशकों को प्रेरित करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे आर्थिक आधुनिकीकरण में देरी हो सकती है।

इसका व्यापार पर भी असर हो सकता है। यूरोपीय संघ और अन्य अर्थव्यवस्थाएँ ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाली वस्तुओं के आयात पर कार्बन शुल्क लगाने का दबाव बना रही हैं, ऐसे में यदि भारत कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योगों पर निर्भर रहता है, तो उसे व्यापारिक अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है, जो निर्यात को प्रभावित कर सकता है। यदि भारत नवीकरणीय ऊर्जा और सततता के लक्ष्यों को कम करता है, तो उसे हरित उद्योगों, जैसे कि सौर पैनल निर्माण में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खोने का खतरा हो सकता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है और इन्फ्रास्ट्रक्चर और तटवर्ती क्षेत्रों को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। जिससे आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान और आपदा पुनर्निर्माण लागतों में वृद्धि हो सकती है।

ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण असामान्य मानसून, सूखा और तेज लू, कृषि उत्पादकता को घटा सकती हैं और सीधे ग्रामीण आय और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव में मंदी से सौर, पवन और अन्य स्वच्छ क्षेत्रों में नौकरियों के सृजन में देरी हो सकती है, जबकि कोयला और तेल उद्योगों पर निर्भरता बनी रह सकती है। जलवायु पर कार्यवाही नहीं करने से आर्थिक हानियाँ-क्षतिग्रस्त इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रदूषण से स्वास्थ्य खर्च और गर्मी के कारण श्रम उत्पादकता में कमी-संशोधित जीवाश्म ईंधन के पक्ष में बने रहने से होने वाली तात्कालिक बचत को पार कर सकती है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600